Faridabad Plot Built
Properties in all Sectors

SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11,
Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential,
Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR
ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping
Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur,
Kasna, Ghaziabad,
Haridawar, Gurgaon,
Manesar, Dharuhera,
Bhiwadi, Vice Varsa

24, Hours Service

Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 अंक 30 सोमवार, फरीदाबाद, 1-15 फरवरी, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

ईएसआई हस्पतालों पर केंद्र ने राज्यों को फटकारा, ठीक से काम करो या काम छोड़ो

नई दिल्ली (म.मो.) केंद्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन डागा ने 22 जनवरी को तमाम राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक में श्रमिकों से संबंधित अन्य मुद्दों के अतिरिक्त ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर गहरी चिंता जताते हुए उन्हें साफ़-साफ़ कह दिया है कि या तो सुधर जाओ या हस्पतालों का काम छोड़ दो ताकि ईएसआईसी इसे स्वयं बेहतर ढंग से कर सके। विदित है कि देश भर के पांच करोड़ से अधिक श्रमिक इस योजना के तहत अपने खून-पसीने की कमाई का साढ़े तीन प्रतिशत भाग ईएसआई को देते हैं जिसके चलते आज इसके पास 19583 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (तमाम खर्चे काट कर) एकत्रित हो चुका है। योजना के अनुसार तमाम राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का संचालन राज्य सरकारें कराती हैं जबकि इन पर होने वाले खर्च का 88 प्रतिशत निगम देती है और शेष 12 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करती हैं। राज्य सरकार को यह रकम इसलिए देनी होती है, क्योंकि राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना इनकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। अपने इसी छोटे से अंशदान के बदले राज्य सरकार पूरी ईएसआई सेवाओं पर चौधर करती है, इन सेवाओं का जैसे मर्ज़ी दुरुपयोग करती है। इसके स्टाफ़ से सरकार वे ड्यूटियां लेती हैं जिनके लिये इन्हें भर्ती नहीं किया गया है। मरीज़ बेचारे डॉक्टर के लिए तरस रहे होते हैं और डॉक्टर सूरजकुंड पर गवर्नर या मुख्यमंत्री के बीमार या घायल होने की स्थिति में उनका इलाज करने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार व मेघालय की सरकारों

जो काम तुरंत कर सकते हैं श्रम मंत्री

औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के करीब तीन लाख मज़दूर परिवारों को राज्य के श्रम मंत्री महेन्द्र प्रताप एक लाभ तो तुरंत दे सकते हैं। पूर्व श्रम मंत्री चौधरी ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज का जो ड्रामा रचा था, उसके लिए उन्होंने 70 डॉक्टरों व 43 नर्सों सहित कुल 202 पोस्टें 26 फरवरी 2009 में स्वीकृत करा ली थी, उनका बजट तुरंत सरकार से मांगा व प्राप्त किया जा सकता है जो उन्होंने नहीं मांगा था। इस बजट की कुल रकम है आठ करोड़ जिसमें से राज्य सरकार को देना है केवल एक करोड़ और शेष सात करोड़ मिलेगा ईएसआई कारपोरेशन से।

श्रम मंत्री यदि थोड़ी सी हिल-डुल कर लें तो राज्य सरकार के मामूली से खर्च पर इस शहर को 70 डॉक्टरों व 43 नर्सों सहित 202 नये कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं, जिनसे शहर भर की डिस्पेंसरियों व दोनों हस्पतालों (एनआईटी नंबर-तीन तथा सेक्टर-8) की स्थिति में भारी बदलाव आ सकता है और ईएसआई में भटकते श्रमिकों व उनके बीमार आश्रितों को बड़ी राहत पहली अप्रैल से ही मिल सकती है।

मंत्री जी के लिये यह समझ लेना भी जरूरी है कि उनके मातहत छोटे-बड़े तमाम बाबुओं की इस तरह के कामों में कतई कोई रुचि नहीं होती। उन्हें तो अपनी नौकरी पीटने व वेतन लेने तक में ही रुचि रहती है। उनकी जनता के प्रति न तो कोई जवाबदेयी होती और ना ही उन्होंने जनता से वोट लेने होते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते यह केवल और केवल मंत्री जी का ही दायित्व है जो जनता के दुख-दर्द की ओर ध्यान देने का समय निकालें।

ईएसआईसी के डीजी ने भी किया हस्पताल का मुआयना

मज़दूर मोर्चा के 1 से 15 दिसंबर के अंक मं ईएसआई हस्पताल व डिस्पेंसरियों की बदहाली तथा वहां आने वाले मरीज़ों की दयनीय स्थिति के साथ-साथ इसके कारणों व निदान की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की गई थी। इस सारी हकीकत को देखने-समझने के लिए राज्य की श्रम वित्तायुक्त सुरीना राजन, ईएसआई के निदेशक डॉक्टर सरना को चंडीगढ़ से लेकर स्वयं 17 दिसंबर को आई थीं।

उस दिन उन्होंने ईएसआई हस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ-साथ ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक ए.के.श्रीवास्तव के एक प्रतिनिधि को भी बैठक में बुलाया था।

स्थानीय डॉक्टरों तथा क्षेत्रीय निदेशक के प्रतिनिधि ने सुरीना राजन को खूब अच्छी तरह आंकड़े देकर समझा दिया था ईएसआई कारपोरेशन की ओर से पैसे देने में कोई कमी नहीं है, सारी हरामखोरी तो चंडीगढ़ स्थित उनके अपने कार्यालय में भरी पड़ी है जो कारपोरेशन के पत्रों पर अमल करना तो दूर, पढ़ना तक गवारा नहीं करते। इसके बाद 30 दिसबंर को ईएसआई कारपोरेशन के महानिदेशक सी.के.केदार भी अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय से चल कर तीन नंबर स्थित ईएसआई हस्पताल पहुंचे।

पूरे हस्पताल का मुआयना करने के बाद वे अपने एक सहयोगी को साथ लेकर लाइनों में लगे मरीज़ों के बीच, उनकी वास्तविक मन:स्थिति जानने के लिए बैठ गये।उस वकत उन्होंने स्वयं महसूस किया कि ईएसआई हस्पताल में आ कर मरीज़ किस तरह कलपते हैं। इसी आधार पर एक रिपोट्र बना कर उन्होंने केंद्रीय श्रम सचिव एवं मंत्री को भेजी, जिसे लेकर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 22 फरवरी, 2009 सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को तलब किया है।

जोती बाबू : एक श्रद्धांजलि

■ **डॉ. लालबहादुर वर्मा**

ज्योति बसु के बारे में दो बातें सबसे अधिक चर्चा में हैं और रहेंगी। एक, जोती बाबू 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और दूसरी यह कि अपनी ही पार्टी के नकारने के कारण भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो पाये, वर्ना सभी पार्टियों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। ऐसा 'स्वीकार्य' कोई दूसरा कम्युनिस्ट नेता नहीं हुआ। ये दोनों बातें उनके मूल्यांकन में जितना पक्ष में खड़ी होती हैं उतनी ही विपक्ष में।

पक्ष में इसलिए कि भारत में किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री इतने दिनों तक शासन नहीं कर पाया है, न ही कम्युनिस्ट जैसी पार्टी, जिसकी सबसे अधिक आलोचना होती है, का नेता होते हुये भी उन बूर्जुआ पार्टियों ने उन्हें देश का प्रधानमंत्रित्व सौंपना स्वीकार लिया था जिनकी कम्युनिस्ट पार्टियां और ज्योति बसु हमेशा कटु आलोचना करते रहे हैं। विपक्ष में यह कि यह दोनों बातें इसलिए संभव हो पाईं, क्योंकि वह भारत की बूर्जुआ राजनीति में समायोजित हो गये थे। उनको और उनकी पार्टी को भारत की किसी भी और पार्टी और नेता की तरह समझा जाता है। कम्युनिस्ट के लिए इससे बड़ी और कोई आलोचना नहीं हो सकती। ज्योति बसु भी भारत में अंग्रेज़ी राज की पैदाइश थे - आधुनिक भारत के सभी क्षेत्रों के अधिकांश नेतृत्व की तरह। वह भी तथाकथित उच्च जाति और संपन्न परिवार में पैदा हुए, विलायत में शिक्षा पाई, वहीं राजनीति की ओर अग्रसर हुए और भारत लौट कर राजनीति में कूद पड़े। कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करने के जोखिम थे-उन्हें उठाया। विविध कठिनाइयों के बीच अपनी जगह बनाई। आज़ाद भारत में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने संसदीय राजनीति करने का निर्णय लिया तो ज्योति बाबू को यह नीति रास आई। जब कम्युनिस्ट पार्टी का पहला विभाजन हुआ तो वह उसके मार्क्सवादी धड़े सीपीएम में चले गये। कुछ ही दिनों में उजागर हो गया कि बात चाहे जितनी बनाई जाये और सिद्धांत चाहे जितना बघारा जाये, दोनों पार्टियों में कोई मूलभूत अंतर नहीं रहा है। उन्नीसवीं सदी में ही जर्मनी में बर्न्सटाइन ने जोर दे कर कहना शुरू कर दिया था कि मेहनतकश का राज संसदीय तरीके से भी कायम हो सकता है और उसके लिए क्रांति की जरूरत नहीं है। लेनिन ने सिद्धांत और व्यवहार में इस लाइन को परास्त कर रूस में क्रांति की थी और उसे स्थायित्व दिया था। पर पश्चिमी यूरोप में 'सोशल डेमोक्रेसी' की हिमायत पार्लियामेंटों में होती रही और ब्रिटेन में लास्की की लाइन पकड़ कर 'लेबर पार्टी' सत्ता में आई और जीतती-हारती आज भी सत्ता में है। धीरे-धीरे दुनिया के अधिकांश देशों में लेबर पार्टी के रास्ते से समाजवाद की बात करने वाले दल विभिन्न मुखौटों के साथ आज भी कार्यरत हैं। ऐसी पार्टियों में भारत की तरह समाजवाद से राष्ट्रवाद तक की बात करने वाली किसिम-किसिम की पार्टियां हैं - कोई मार्क्सवाद का नाम लेता है, कोई नहीं, पर समाजवाद की बात सभी करते हैं - कम्युनिस्ट, समाजवादी और कांग्रेस। पार्टियों के कई-कई धड़े। 1949 में चीनी क्रांति के बाद जल्दी ही कम्युनिस्ट आंदोलन का तेज़ी से ध्रुवीकरण शुरू हो गया था जो सोवियत यूनियन के विघटन और चीनी पार्टी के बाज़ारवादी हो जाने के बाद और तेज़ हो गया है, एक ओर उग्र माओवाद और दूसरी ओर उदारवादी समाजवाद। ज्योति बसु दूसरी धारा में बहते-बहते घाट उतर गये थे। वास्तव में, सामान्यत: सारी दुनिया में और विशेष रूप से भारत में, कोई भी कम्युनिस्ट कोई भी 'लाइन' लागू करता नहीं दिख रहा है-न मार्क्स की लाइन, न लेनिन की लाइन न माओ की। कोई किसी 'मार्गदर्शक' को ठीक से समझता भी नहीं लगता। भारत के कम्युनिस्टों के आचार-व्यवहार-विचार से तो यह लगता है कि वे रूसी, चीनी या क्यूबाई क्रांति को न ठीक से समझते हैं, न अपनी समुचित लाइन विकसित करने में सक्षम हैं।

ज्योति बसु : व्यवस्था से बेहतर तालमेल बिठाया

ज्योति बसु ने विद्रोही कांग्रेसियों के साथ संयुक्त सरकार बनाई थी और नक्सलवाद के दमन में गृह मंत्रालय की पूरी ताकत लगा दी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू में उन्होंने भारत के किसी भी राज्य से आगे जा कर भूमि-सुधार किये और कलकत्ते में मज़दूरों का इतना बोलबाला हुआ कि हड़ताल और घेराव रोज़ की बात हो गई। कलकत्ता भारत में उद्योग-व्यवसाय की अगुआई करता था। वहां से पूंजी और पूंजीवादियों का पलायन शुरू हो गया था। पर कुछ ही दिनों में सीपीएम ने भारत की सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया गुर्गे बनाने में। सीपीएम पश्चिम बंगाल में विदेशी पूंजी का आह्वान करती थी और केंद्र में भूमंडलीकरण का विरोध। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो दोहरापन पूरी तरह उजागर हो गया - एक ओर सीपीएम के समर्थन से सरकार चलती रही और नई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत आत्मसात होता रहा और दूसरी ओर उसकी सभी नीतियों का ज़बानी विरोध चलता रहा। और अंतत: अवसरवादी ढंग से समर्थन वापस ले लिया गया। कहते हैं ज्योति बाबू इसके पक्ष में नहीं थे।

- **शेष पेज 2 पर**